

(6)

# न्यायालय तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़

करण संख्या 18/2019

## सरकार जरिये पटवारी हल्का

बनाम

..... रामकुमार ..... पुत्र ..... रामपुताप .....  
जाति ..... विशनाई ..... साकिन ..... 755M-B ..... निर्णय दिनांक 1.5.2019 .....

इस प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं :-

पटवारी हल्का ..... 755M-A ..... ने इस न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि चक ..... 755M-B ..... के मु. नं. 264/374 ..... के कि. नं. .... के कुल ..... 6.072 है ..... रकबा राज पर ..... रामकुमार ..... पुत्र ..... रामपुताप ..... जाति ..... विशनाई ..... साकिन ..... 755M-B ..... ने फसल रबी/खरीफ में जिन्स रकबा पर ~~है, खरीफ, यन्त्र, फसल~~ काशत कर अतिक्रमण कर लिया है।

पटवारी के आवेदन को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी प्रारूप में नोटिस जारी किया गया। नोटिस में विनिर्दिष्ट भूमि का अंकन कर अप्रार्थी से यह आपेक्षा की गई थी, कि वह निर्धारित तिथि तक इस भूमि से अपना अधिभोग हटा लें, अन्यथा उपस्थित आकर ऐसा न करने का कारण बतावें। नोटिस अप्रार्थी पर विहित रिति से तामिल हुआ।

नोटिस के प्रत्युत्तर में, अप्रार्थी दिनांक 3/4/19 ..... को उपस्थित आया। उसने लिखित जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार प्रशनगत भूमि रकबा राज हैं। अप्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई उपयुक्त कारण नहीं बताया है जिसके आधार पर उक्त भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा विधिपूर्ण साबित हो। अतः अप्रार्थी ..... रामकुमार ..... पुत्र ..... रामपुताप ..... को चक ..... 755M-B ..... के मु. नं. 264/374 ..... के ..... 6.072 है ..... रकबा राज को विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अधियोग में लेने के कारण अतिधारी किया जाता है। इस अतिधार के लिये उस पर भू-राजस्व का ..... दस ..... गुणा रूपये ..... 566 ..... अखरे रूपये ..... पांच सौ ..... रुपये ..... मात्र की शास्ती आरोपित किया जाता है भू. अभि. निरीक्षक को पूर्व में उक्त रकबे पर काशत फसल को कुर्क करने के अन्तरिम आदेश दिये गये थे, उसकी पुष्टि कि जाती है। भू. अभि. निरीक्षक को आदेश जारी हो कि कुर्क फसल सरेआम निलाम कर, बाद अनुमोदन राशि राजकोष में जमा करावें।

पटवारी हल्का को आदेश जारी हो कि शास्ती की मांग ढालबाछ में कायम, वसूली करें तथा अप्रार्थी को उक्त रकबा राज से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लेवे। T.R.A. के 'घ' रजिस्टर में मांग कायम करावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब व तफसील दाखिल दफ्तर हो।

(निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।)